



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7]

नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जनवरी 11, 2007/पौष 21, 1928

No. 7]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 2007/PAUSA 21, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2007

विषय : अमरीका, कोरिया गणराज्य तथा ताईवान से फेनॉल के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

सं. 14/5/2006 डीजीएडी.—जबकि मै0 हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कॉमिकल्स लिमिटेड तथा मै0 एस आई ग्रुप-इंडिया लि�0 (जिसका नाम पहले शेनेकटेडी हर्डिलिया लिमिटेड था) ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात पाटनरोधी नियम कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें अमरीका, कोरिया गणराज्य एवं ताईवान (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनॉल (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पाटनरोधी जांच करने एवं इस प्रकार के पाटित संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

और जबकि प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग की क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य उपस्थित हैं और वे एतद्वारा किसी कथित पाटन की उपस्थिति, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे यदि लागू किया जाए तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन एवं परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच प्रारंभ करते हैं।

2. विचाराधीन उत्पाद

प्रस्तावित पाटनरोधी जांच में विचाराधीन उत्पाद फेनॉल एक आधारभूत कार्बनिक रसायन है जिसे सामान्यतः सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, इसके आयात अध्याय 27 के अंतर्गत भी सूचित किए जाते हैं। इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष सं0 2907.11 तथा 2707.60 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण मात्र सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच पर बाध्यकारी नहीं है।

इस उत्पाद का विपणन क्रिस्टलाइन एवं हाइड्रेटेड दो ग्रेडों में किया जाता है। इन दोनों ग्रेडों को फेनॉल की प्रवाह संबंधी विशेषताओं के आधार पर अलग-अलग किया जाता है। इस उत्पाद का दो रूपों में विपणन किया जाता है - खुला और पैकड़। खुले रूप में इसकी बिक्री सामान्यतः बड़ी मात्रा में की जाती है जबकि पैकड़ परेषण काफी छोटे कंटेनर भार के हो सकते हैं। फेनॉल का प्रयोग फेनॉल फार्मलडिहाइड रेजिन्स, लेमिनेट्स, प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड, बिसफेनॉल-ए अल्काइल फेनॉल भेषजों, डिफिनाइल आक्साइड आदि के विनिर्माण में किया जाता है।

3. घरेलू उद्योग और उसकी योग्यता

यह याचिका मै0 हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड और मै0 एस आई ग्रूप इंडिया लि�0 (जिसे पहले सेनेकटेडी हरदीलिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है। यह पाया गया है कि मै0 एस आई ग्रूप-इंडिया लि�0 (जिसे पहले सेनेकटेडी हरदीलिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ने संबद्ध देश (देशों) से संबद्ध वस्तु के भारी मात्रा में सीमाशुल्क प्रदत्त आयात किए हैं। प्राधिकारी ने मै0 एस आई ग्रूप-इंडिया लि�0 (जिसे पहले सेनेकटेडी हरदीलिया लि�0 के नाम से जाना जाता था) को "घरेलू उद्योग" के दायरे से बाहर रखना उचित समझते हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ हिन्दुस्तान आर्गेनिक कंपनी लि�0 को "घरेलू उद्योग" माना जाएगा।

उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार आवेदक के पास पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) (क) के अनुसार पाटनरोधी जांच के लिए मामला दायर करने संबंधी योग्यता है।

4. समान वस्तु

याचिकाकर्त्ताओं का यह दावा है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित फेनॉल और संबद्ध देशों से निर्यातित फेनॉल के बीच कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित फेनॉल और संबद्ध देशों से आयातित फेनॉल भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं और इनमें काफी मिलती-जुलती विशेषताएं हैं। आगे यह दावा किया गया है कि उपभोक्ता इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उत्पादित फेनॉल को पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित फेनॉल के समान उत्पाद माना जा रहा है।

5. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश यू.एस.ए, कोरिया गणराज्य (कोरिया आर पी) और ताईवान हैं (जिन्हें संबद्ध देश भी कहा गया है)।

6. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्त्ताओं ने यू.एस.ए के मामले में मालभाड़े और बीमा के लिए समायोजन के पश्चात (आई सी आई एस-एल ओर आर पत्रिका के आधार पर), घरेलू कीमत के आधार पर और कोरिया गणराज्य तथा ताईवान के लिए जहाँ अपेक्षित हो भारतीय अनुभव के आधार पर प्रमुख निविष्टियों तथा अन्य ऊपरी अनुमानों की प्रकाशित कीमतों पर विचार करते हुए उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। इसमें शामिल भारी पैकिंग लागत को ध्यान में रखते हुए खुले और पैक की गई सामग्री के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

7. निर्यात कीमत

निर्यात कीमत डी जी सी आई एण्ड एस से एकत्रित सौदा वार सूचना पर आधारित है। इसके अलावा खुले और पैक की गई सामग्री के लिए अलग-अलग निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। चूंकि इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत सी आई एफ स्तर पर है इसलिए कारखाना द्वारा पर निर्यात कीमत के निर्धारणार्थ इसे समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, निर्यात के देश में अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन व्ययों, ऋण लागत, कमीशन तथा बैंक के कमीशन पर हुए व्ययों के लिए समायोजित किया गया है।

8. पाटन मार्जिन

इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक हैं जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

9. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्त्ताओं ने उत्पादन, बिक्री मात्राओं, क्षमता उपयोग, लाभ, लगाई गई पूँजी पर आय, नकद लाभ, बाजार हिस्से, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री आदि की दृष्टि से उनकी स्थिति में काफी विकृति आने के कारण कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं कि याचिकाकर्त्ताओं को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति उठानी पड़ रही है।

10. जांच अवधि (पी ओ आई)

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पी ओ आई) जुलाई, 2005 - जून, 2006 तक की है। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2003 - मार्च, 04, अप्रैल, 2004 - मार्च, 2005, अप्रैल, 2005 से मार्च, 2006 की अवधि तथा जांच अवधि शामिल होगी।

11. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। वर्तमान जांच में भाग लेने का इच्छुक कोई अन्य पक्षकार भी निम्नलिखित पते पर अपने अनुरोध भेज सकता है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी)
कमरा सं. 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली- 110011

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी जांच से संगत अपने अनुरोध नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रस्तुत कर सकती है।

12. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिन) से पूर्व पहुँच जानी चाहिए। तथापि ज्ञात निर्यातकों एवं आयातकों जिहें अलग से लिखा गया है, को यह सूचना उन्हें भेजे गए पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर भेजनी होगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त हुई सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

13. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

नियम 7 के अनुसार, हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी के समक्ष किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना होगा और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश करना संभव नहीं है तो इसके कारणों संबंधी विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं।

यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं करती है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2007

Subject : Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning the imports of Phenol from USA, Korea RP and Taiwan

No. 14/5/2006 DGAD.— Whereas M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited and M/S S I Group-India Ltd (Formerly known as Schenectady Herdillia Limited) have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of anti dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as AD Rules), alleging dumping of Phenol (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from USA, Republic of Korea and Taiwan (hereinafter referred to as the subject countries) and have therefore requested for initiation of an anti-dumping investigation against the imports of the subject goods from the subject countries and levy anti-dumping duty on the such dumped subject goods.

AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods by the subject countries, injury to the domestic industry and causal links between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

2. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The Product under consideration in the proposed anti-dumping investigation is Phenol. Phenol is a basic organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. However, imports are reported under Chapter 27 also. The product is classifiable under Customs Tariff heading no. 2907.11 and 2707.60. The Customs classifications are, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

The product is marketed in two grades Crystalline and Hydrated. The two grades are differentiated on the basis of flow characteristics of Phenol. The product is marketed in two forms - loose and packed. Loose sales are normally in bulk, whereas packed consignments can be of much smaller container loads. Phenol is used in the manufacture of Phenol formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A alkyl Phenols Pharmaceuticals, Dephenyl Oxide etc.

124 GI/07-2

3. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

The petition has been jointly filed by M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited and M/S S I Group-India Ltd(Formerly known as Schenectady Herdillia Limited). There are no other known producers of the product in the Country. It is found that M/S S I Group-India Ltd(Formerly known as Schenectady Herdillia Limited)has made significant customs duty paid imports of the subject goods from subject country(ies). The Authority has considered it appropriate to exclude M/S S I Group-India Ltd(Formerly known as Schenectady Herdillia Limited from the scope of the "domestic industry". Hindustan Organic Chemicals Limited shall constitute "domestic industry" for the purpose of the present investigations.

As per the evidence available, applicant has the standing to file the case for anti dumping investigation on behalf of domestic industry as per Rule 2(b) and Rule 5(3)(a) of Anti Dumping Rules.

4. LIKE ARTICLE

Petitioners have claimed that there is no significant difference in Phenol produced by the domestic industry and Phenol exported from subject countries. Phenol produced by the domestic industry is comparable to phenol imported from subject countries in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Both the products are technically and commercially substitutable and hold closely resembling characteristics. It is further claimed that the consumers have used the two interchangeably. For the purpose of present investigation, phenol produced by the petitioners is being treated as like article to phenol imported from subject countries within the meaning of the Anti Dumping Rules.

5. COUNTRIES INVOLVED

Countries involved in the present investigations are USA, Republic of Korea (Korea RP) and Taiwan (also referred to as subject countries).

6. NORMAL VALUE

Petitioners have claimed normal value on the basis of domestic price (based upon ICIS-LOR magazine) after adjustment for freight and insurance in the case of USA and on the basis of estimates of cost of production by considering the published prices of major inputs and other overhead estimates on the basis of Indian experience wherever required in case Korea and Taiwan. Separate normal value has been determined for loose and packed material in view of significant packing cost involved.

7. EXPORT PRICE

Export price is based on transaction wise information collected from DGCI&S, Further, separate export price has been determined for loose and packed material.

Since the export price so determined is at CIF level, the same has been adjusted for expenses on account of ocean freight, marine insurance, inland transportation in the country of export, port expenses, credit cost, commission and bank commission to arrive at the ex-factory export price.

8. DUMPING MARGIN

There is sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries.

9. INJURY AND CAUSAL LINK

Petitioners have furnished evidence regarding injury having taken place as a result of the alleged dumping in terms of significant deterioration in terms of production, sales volumes, capacity utilization, profits, return on capital employed, cash profits, market share, price undercutting, price underselling, etc. There is sufficient prima-facie evidence of material injury being suffered by the petitioners caused by dumped imports from subject countries.

10. PERIOD OF INVESTIGATION (POI):

The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is July, 2005 - June, 2006. The injury investigation period will however, cover the period April, 2003-March, 04, April, 2004-March, 05, April, 2005-March, 06 and period of investigation.

11. SUBMISSION OF INFORMATION:

The exporters in the subject countries and their Government through their embassies/representatives in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

12. TIME LIMIT

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty (40) days

from the date of publication of this notification, The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within (40) forty days from the date of the letter addressed to them. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

13. SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

In terms of Rule 7, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided.

14. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6 (7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

CHRISTY L FERNANDEZ, Designated Authority